

बीमारु से बेमिसाल बना उत्तर प्रदेश

कैग रिपोर्ट की सच्चाई, रेवेन्यू सरप्लस में **गुजरात को पीछे छोड़कर** नंबर वन बना यूपी

नई दिल्ली, प्रैट्र: कभी बीमारु राज्य का दर्जा पाए और पिछड़ेपन व आर्थिक तंगी की वजह से चर्चा में रहनेवाले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने आर्थिक मोर्चे पर बढ़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत के महालेखाकार (कैग) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस में अव्वल रहा। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की आमदनी खर्चों से ज्यादा रही। प्रदेश के पास साल 2023 में सबसे ज्यादा 37 हजार करोड़ की बचत पाई गई। खास बात ये रही कि इस सूची में उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश ने भी टाप 10 में जगह बनाई है।

कैग ने पहली बार राज्यों के वित्त स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें पिछले एक दशक में राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन का अध्ययन किया गया है। कैग ने पाया कि 16 राज्यों का राजस्व अधिशेष यानी आमदनी से खर्च को घटाने के बाद की बचत ज्यादा रही। सूची में छत्तीसगढ़, छठवें और उत्तराखण्ड आठवें स्थान पर रहे। पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम भी इस सूची में शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 राज्य ऐसे थे, जिनका खर्च उनकी आमदनी से ज्यादा पाया गया। ऐसे राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल शामिल थे। इन 12 राज्यों



● उत्तर प्रदेश ने भी लगाई लंबी छलांग, बिहार पिछड़ा

16 राज्यों की कमाई ज्यादा और खर्च करा कम

12 राज्यों का खर्च आमदनी से ज्यादा पाया गया



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ● फाइल

किस राज्य के पास कितना सरप्लस (करोड़ रुपये में)

उत्तर प्रदेश	37,263
गुजरात	19,865
ओडिशा	19,456
झारखण्ड	13,564
कर्नाटक	13,496
छत्तीसगढ़	8,592
तेलंगाना	5,944
उत्तराखण्ड	5,310
मध्य प्रदेश	4,091
गोवा	2,399



राज्यों ने अपने दम पर कितनी की कमाई

हरियाणा	80%
तेलंगाना	79%
महाराष्ट्र	73%
गुजरात	72%
कर्नाटक	69%
तमिलनाडु	69%
गोवा	68%

अनुदान पानेवाले फिसड़डी राज्यों का हिस्सा

पश्चिम बंगाल	15.76%
केरल	15.28%
आंध्र प्रदेश	12.24%
हिमाचल	10.88%
पंजाब	9.60%
उत्तराखण्ड	8.28%
असम	5.67%
राजस्थान	5.64%
नागालैंड	5.26%
त्रिपुरा	5.13%

अपने दम पर कमाई वढ़ाने में हरियाणा अव्वल

सीएजी रिपोर्ट में कुछ राज्य ऐसे भी बताए गए हैं, जिन्होंने अपनी टैक्स और गैर-टैक्स आय को मजबूत किया है। इसमें हरियाणा ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां राज्य की कुल आय का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा उसकी खुद की कमाई से आता है। इसके बाद तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, और गोवा ने केंद्र पर निर्भरता कम करते हुए अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत किया है।

का संयुक्त राजस्व घाटा 2,22,648 करोड़ रुपये रहा। इन राज्यों का राजस्व घाटा पाठने के लिए, वित्त आयोग की तरफ से 86,201 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया, जो

कुल राजस्व घाटे का 39 प्रतिशत था। राजस्व घाटा अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल को मिला। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब,

यूपी अब बीमारु राज्य नहीं है। यह रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने के साथ ही इस श्रेणी के राज्यों में शीर्ष पर है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय और जीएसडीपी तेजी से बढ़ी है। राज्य का निर्यात तेजी से बढ़ा है। 22 प्रतिशत की दर से औद्योगिक विकास हो रहा है। वित्तीय अनुशासन में यूपी सभी राज्यों से बेहतर है।

- सुरेश कुमार खना, वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश

उत्तराखण्ड, असम, राजस्थान, नागालैंड और त्रिपुरा को मिला। इन 10 राज्यों ने कुल वित्त आयोग के राजस्व घाटा अनुदानों का लगभग 94 प्रतिशत प्राप्त किया।